

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Friday, 25 September 2026

खुशखबरी ! 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद बढ़ेगी सैलरी, जाने कंब से मिलेगा लाभ ।

Publisher

Published on 14 Jul 2025



जनवरी 2026 से लागू हो सकता है **8वां वेतन आयोग**, सरकारी कर्मचारियों और पेशनभोगियों की सैलरी में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी संभव ।

नई दिल्ली : देश के 44 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेशनभोगी लंबे समय से जिस फैसले का इंतजार कर रहे थे, वह अब धीरे-धीरे मूर्त रूप ले रहा है । इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार ने **8वे वेतन आयोग** के गठन को मंजूरी दे दी थी, जिसका उद्देश्य वेतन और पेशन ढांचे को दोबारा निर्धारित करना है ।

हालांकि फिलहाल इसका आधिकारिक ऐलान बाकी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस आयोग की सिफारिशें **2025 के अंत तक** सरकार को सौंपी जा सकती हैं, और इसे **जनवरी 2026** से लागू करने की संभावना जताई जा रही है ।

8वे वेतन आयोग की सिफारिश कब होगी लागू ?

रिपोर्ट के मुताबिक, यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है, तो **आठवां वेतन आयोग 2026** के शुरुआती महीनों में लागू किया जा सकता है । हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इसे **वित्त वर्ष 2027** से प्रभावी करने पर भी विचार कर सकती है ।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वेतन आयोग की सिफारिशें **केन्द्र सरकार की मंजूरी और समयबद्ध कार्रवाई** पर निर्भर करती हैं ।

कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेशन ?

रिपोर्ट के मुताबिक, **केन्द्रीय कर्मचारियों और पेशनभोगियों के वेतन/पेशन में करीब 30 से 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी** हो सकती है । इस बढ़ोतरी से सरकार पर **1.80 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ** पड़ने का अनुमान है ।

यह बढ़ोतरी **फिटमेंट फैक्टर, महंगाई दर, और कर्मचारियों की ज़रूरतों** को ध्यान में रखते हुए की जाएगी ।

वेतन आयोग क्यों होता है जरूरी ?

हर 10 साल में केन्द्र सरकार वेतन आयोग का गठन करती है ताकि:

१. महंगाई और जीवन स्तर में बढ़ोतरी को वेतन में समायोजित किया जा सके
२. कर्मचारियों को बेहतर भत्ते, बोनस और सुविधाएं दी जा सकें
३. वित्तीय असमानता और संतुलन को ठीक किया जा सके
४. देश की अर्थव्यवस्था और बजट संतुलन को भी ध्यान में रखा जा सके
५. पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था और तब से लेकर अब तक यह 8वीं बार वेतन समीक्षा प्रक्रिया की जा रही है।

कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया

कई कर्मचारी यूनियनों और फेडरेशनों ने सरकार से मांग की है कि आठवां वेतन आयोग जल्द से जल्द लागू किया जाए और वेतन-भत्तों की समीक्षा इस बार पहले से अधिक न्यायसंगत और व्यापक हो। साथ ही, रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए भी विशेष राहत की मांग की गई है।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.